



:: आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ::
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan,
रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,
राजकोट / Rajkot - 360 001



सत्यमेव जयते

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: comrapp13-cexamd@nic.in

रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा :-

DIN-20221164SX0000999D49

क अपील / फाइल संख्या /
Appeal / File No.
V2/525 / RAJ/2021

मूल आदेश संख्या /
OIO No.
23/JC(MAN)/2021-22

दिनांक /
Date
30-09-2021

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

RAJ-EXCUS-000-APP-356-2022

आदेश का दिनांक /
Date of Order:

28.10.2022

जारी करने की तारीख /
Date of issue:

02.11.2022

श्री शिव प्रताप सिंह, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by Shri Shiv Pratap Singh, Commissioner (Appeals), Rajkot.

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर,
राजकोट / जामनगर / गांधीधामा द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सुजित: /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central
Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ अपीलकर्ता/प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of the Appellant & Respondent :-

**M/s. N.J.Construction, Vrujdham, Lal Bahadur Society, Street No. 3, Plot
No. 10B, Dhebar Road (South), Opp. Jakat Naka, Rajkot**

इस आदेश (अपील) में स्पष्टित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दाखल कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following
way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के
अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है। /

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section
86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) सर्वोच्च न्यायालय से सम्बन्धित सभी मामलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली, को भी जाननी चाहिए। /

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New
Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की
पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहुमाली भवन असावा अहमदाबाद- 380016 को भी जाननी चाहिए। /

To the West regional Bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor,
Bhaumali Bhawan, Asawa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए
गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहाँ उत्पाद शुल्क की योग्यता, व्याज की योग्यता और
लगाया गया जुर्माना, रुपये 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपये या 50 लाख रुपये तक अथवा 50 लाख रुपये से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये,
5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक
रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहाँ संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के
साथ 500/- रुपये का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of
Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be
accompanied by a fee of Rs. 1,000/-, Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty
demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of
crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where
the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.
Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवली, 1994, के नियम 9(1) के तहत
निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकती है एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से
एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहाँ सेवाकर की योग्यता, व्याज की योग्यता और लगाया गया जुर्माना, रुपये 5
लाख या उससे कम, 5 लाख रुपये या 50 लाख रुपये तक अथवा 50 लाख रुपये से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा
10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक
रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस
शाखा में होना चाहिए जहाँ संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपये
का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed
in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be
accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be
accompanied by a fee of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is
Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more
than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest
demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the
Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is
situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.



- (i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकती एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा संलग्न आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी।
The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जमाना विवादित है, या जमाना, जब केवल जमाना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि देय करीब रूप से अधिक न हो।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है
(i) धारा 11 की के अंतर्गत रकम
(ii) सेनवेट जमा की भी गई गलत राशि
(iii) सेनवेट जमा निवामावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं-2) अधिनियम 2014 के अंश से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगा।
For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,
Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include:
(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.
- (C) भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अर्बन सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन इकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जेजवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए।
A revision application lies to the Under Secretary to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:
(i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, बड़ा नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या किसी किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में।
In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
(ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर अभी नई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है।
In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of an excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है।
In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
(iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो क्रेडिट के तहत इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं-2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तरीक अथवा समयावधि पर या बाद में पारित किए गए हैं।
Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमवाली 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संघर्ष के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदावगी के साथ के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-in-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदावगी की जानी चाहिए।
जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए।
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
(D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपरोक्त वंश से किया जाना चाहिए। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पत्रों कार्य से बचने के लिए बचावस्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
(E) बचावस्थिति न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।
One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
(F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमवाली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबंधित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।
Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
(G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbcc.gov.in को देख सकते हैं।
For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbcc.gov.in



अपील आदेश /ORDER-IN-APPEAL

M/s N.J. Construction, Vrujdham, Lal Bhadur Society, Street No.3, Plot No.10B, Dhebar Road (South), Opp. Jakat Naka, Rajkot (*hereinafter referred to as 'Appellant'*) has filed Appeal No. V2/525/RAJ/2021 against Order-in-Original No. 23/JC(MAN)/2021-22 dated 23.09.2021 (*hereinafter referred to as 'impugned order'*) passed by the Joint Commissioner, Central Excise & CGST, Rajkot (*hereinafter referred to as 'adjudicating authority'*).

2. The facts of the case, in brief, are that as per data received from the Income Tax Department, the appellant appeared to have received various amounts as consideration for providing taxable service. It appeared that the appellant had not obtained registration under Service Tax Rules and did not pay service tax on the consideration received for providing taxable service. The appellant, in spite of being asked by the jurisdictional officer, did not produce any details or information about the nature of service provided by them.

2.1 Based on the data provided by the Income Tax department, a Show Cause Notice No. V.ST/Div-I/JC/AS/14/2020-21 dated 28.09.2020 was issued to the Appellant calling them to show cause as to why the value of taxable services provided by them during the period F.Y. 2014-15, 2015-16 and 2016-17 should not be assessed/determined at Rs.6,66,78,336/- under Section 72 of the Finance Act, 1994 and service tax amount of Rs. 93,23,820/- should not be demanded and recovered from them under proviso to Section 73(1) of the Act, along with interest under Section 75 of the Act, and proposing imposition of penalty under Sections 77 and 78 of the Act.

2.2 The above Show Cause Notice was adjudicated vide the impugned order whereunder the adjudicating authority dropped the demand for Rs.87,60,653/- and confirmed the demand of Rs.5,63,653/- under proviso to Section 73(1) of the Finance Act, 1994 along with interest under Section 75 of the Act. He also imposed penalty of Rs.5,63,653/- under Section 78 and Rs. 10,000/- under Section 77(1)(a), Rs. 10,000/- under Section 77(1)(c) and Rs.10,000/- under Section 77(2) of the Finance Act, 1994.

3.1 Being aggrieved, the Appellant has filed the present appeal contending, *inter alia*, that the service tax demanded in the order of Rs.5,19,465/- was on the allegation that the construction of Box Culvert is separate civil structure and hence service tax is leviable. The appellant submitted that Box Culvert constructed are attached to the road and is going to be used for road transportation and as per rule of classification, box culvert should be at par with bridges only. The appellant submitted that as per Section 4 of the National



Highways Act 1956, highways include culverts.

3.2 The appellant submitted that service tax demand of Rs.44,188/- on alleged unexplained income of Rs.2,94,584/- was due to negligence on the part of adjudicating authority as he has not referred to the audit report as well as reconciliation submitted by the appellant on 01.10.2020. The appellant submitted that the difference is other income derived in the form of interest as mentioned in Schedule XIV of Audit Report of FY-16-17. The appellant submitted that no interest is payable and no penalty is imposable for the reason that demand of service tax is not sustainable.

4.1 Personal hearing was held on 12.10.2022 when Shri Ravi Tanna, Chartered Accountant, appeared on behalf of the Appellant. He reiterated the submission made in Appeal Memorandum. He drew attention to the definition of Highways as per Section 4 of the National Highways Act, 1956 which mentions that highways include culverts and contended that their work order specifically mentioned culverts for state highways. He undertook to submit diagrams/photographs of the said culverts post hearing. He also contended that the unexplained income mentioned in the order of adjudicating authority was actually interest on the Fixed Deposits. He undertook to submit extracts of the audit report, form 26AS, bank statement etc., in this regard. Based on these contentions he requested to drop the demand, interest and penalty.

4.2 Vide letter dated 15.10.2022, the appellant submitted copies of work orders of R & B Porbandar, R & B Junagadh and photographs of box culverts, extracts of the audit report, form 26AS and bank statement.

5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, grounds of appeal in the appeal memorandum and oral as well as written submissions made by the Appellant. As per the facts available on record, the demand was made on the on the basis of data provided by the Income Tax department. Though the documents related to the income shown in the returns of Income Tax department were called for by the jurisdictional CGST officer, the appellant did not provide them. However, the appellant has submitted the documents at the time of adjudication. From the work order, the adjudicating authority found that the appellant had provided construction services to the Government/local authority and provided services viz. construction of road, bridge, box culvert, slap, Fire Brigade Station. The adjudicating authority has observed that the service provided by appellant were exempted. However, the adjudicating authority has held that 'box culvert' is unique 'civil structure' and cannot be termed as part of the road or bridge and hence confirmed the demand of service tax to the extent of service provided in respect of construction of 'box



Handwritten signature

culvert'. The adjudicating authority has also confirmed the demand of service tax to the tune of Rs.44,188/- on unexplained income of Rs.2,94,584/-. Thus issue to be decided in this case is whether the impugned order, in the facts and circumstances of the case, confirming the demand against the service of construction of 'box culvert' and 'unexplained income' with penalty is legal and proper.

6. The contention of the appellant, in this regard, is that 'Box Culvert' constructed are attached to the road and is going to be used for road transportation and as per rule of classification, box culvert should be at par with bridge only. The appellant submitted that as per Section 4 of the National Highways Act 1956, highways include culverts. In this regard, I find that, the adjudicating authority has not given any valid reason for not considering 'box culvert' as part of road. On the contrary, Section 4 of the National Highway Act, 1956 considered bridges, culverts, tunnels, causeways, carriageways and other structures constructed on or across highways as 'highways'. Section 4 of the National Highway Act, 1956 reads as under:

"4. National highways to vest in the Union.—All national highways shall vest in the Union, and for the purposes of this Act "highways" include—

(i) all lands appurtenant thereto, whether demarcated or not;

(ii) all bridges, culverts, tunnels, causeways, carriageways and other structures constructed on or across such highways; and

(iii) all fences, trees, posts and boundary, furlong and milestones of such highways or any land appurtenant to such highways."

7. From the above, it is evident that culverts are considered as integral part of highways under National Highway Act. 1956. Even the dictionary meaning of culvert reads as '**a drain or channel crossing under a road, sidewalk, etc.**' (Dictionary.com)'. As such, I am of the considered view that culverts are parts of road and the service provided by constructing 'box culvert' can be considered as service provided in respect of construction of road which is exempted as per Sr. No.13(a) of Notification No.25/2012-ST. Further, the work order is specifically for construction of 'box culvert on Thoyaba-Jamby Kerala-Badopar Road and Manavadar Jilna Buri Road'. Thus, it transpires that the work carried out by the appellant by way of construction of 'box culvert' is to be considered as a part of road and hence eligible for exemption per Sr. No.13(a) of Notification No.25/2012-ST.

8. Regarding the confirmation of demand of service tax on 'unexplained income amount of Rs.2,94 584/-', I find that the adjudicating authority has failed to correlate or establish the said amount as a consideration in respect of any service provided by the appellant. On the contrary, the appellant has submitted unexplained income of Rs.2,94,584/- was towards receipt of interest. I



[Handwritten signature]

also find that the appellant has submitted a reconciliation statement and copy of balance sheet, audit report etc. before the adjudicating authority. On perusal of the said reconciliation statement and profit and loss account, I find that the income of Rs.2,94,584/- in 2016-17 was towards interest income and hence not taxable. Thus, the impugned order to the extent of confirming the demand of service tax is not sustainable on merits. As the demand is not sustainable, there is no question of charging interest and imposing penalty in this regard.

9. In view of the above, I allow the appeal and set aside the demand of service tax of Rs.5,63,653/-, with entire penalty under Section 78, Section 77(1)(a), Section 77(1)(c) and Section 77(2) of the Finance Act, 1994 imposed on the appellant by the adjudicating authority.

१०. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

10. The appeal filed by the Appellant is disposed off as above.

सत्यापित / Attested

Joseph

Superintendent

By R.P.A.D. Central GST (Appeals)
Rajkot

Shiv Pratap Singh
28/10/2022

(शिव प्रताप सिंह/ SHIV PRATAP SINGH)
आयुक्त (अपील)/Commissioner (Appeals)

सेवा में, मे० एन। जे कन्स्ट्रक्शन वृजधाम, लाल बहादुर सोसाइटी, स्ट्रीट No.3, प्लॉट नो.10बी ढेबर रोड, (साउथ) ओप्प। जकात नाका, राजकोट	To M/s N.J. Construction, Vrujdham, Lal Bhadur Society, Street No.3, Plot No.10B, Dhebar Road (South), Opp. Jakat Naka, Rajkot
---	---

प्रतिलिपि :-

- 1) मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, राजकोट को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) ऊप आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट -I मंडल, राजकोट आयुक्तालय, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) गार्ड फाइल।

